उज्जैन भूमि सौदों की न्यायिक जांच की मांग

विशेष रिपोर्ट के बाद सरकार निशाने पर

जीतू पटवारी

उमंग सिंघार

मुकेश नायक

विशेष संवाददाता

भोपाल, 23 जून.मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में कथित बड़े पैमाने पर हुई भूमि खरीद-फरोख्त की स्वतंत्र एवं न्यायिक निगरानी में जांच कराने की मांग करते हुए राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं और भूमि सौदों के बीच संभावित हितों के टकराव पर सवाल उठाए हैं.

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री से उन आरोपों पर स्पष्टीकरण देने की मांग की, जिनमें उनके परिवार से जुड़े व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा भूमि खरीदे जाने की बात कही गई है. पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे भी उपस्थित रहे.

जीतू पटवारी ने द इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट और सार्वजनिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि उज्जैन एवं आसपास के क्षेत्रों में लगभग 245 प्लॉटों में फैली 335 एकड़ भूमि कथित रूप से मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े व्यक्तियों और कंपनियों के नाम दर्ज है. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच करीब 253 एकड़ भूमि खरीदी गई, जिसमें केवल 2024-25 के दौरान 137 प्लॉटों में 168 एकड़ भूमि शामिल है.

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की भूमि का पूरा विवरण सार्वजनिक करने तथा विकास परियोजनाओं और भूमि खरीद के बीच संभावित संबंधों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. पार्टी ने कहा कि वह जनहित में इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी.

> पटवारी ने कहा कि सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि जिन क्षेत्रों में बाद में सड़क, बायपास, कॉरिडोर और अन्य विकास परियोजनाओं की घोषणाएं हुईं, उन्हीं इलाकों में बड़े पैमाने पर भूमि खरीद की खबरें सामने आईं. उन्होंने उज्जैन-बदनावर रोड, उज्जैन-इंदौर रोड, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग, उज्जैन-मक्सी रोड, उज्जैन-नागदा रोड, उज्जैन-देवास रोड तथा प्रस्तावित गरोठ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का उल्लेख किया.

> उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि इस मामले ने शासन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार भूमि खरीद में लगातार वृद्धि हुई और इसमें सिद्धिविनायक देवकॉन्स, मंगलमूर्ति इंफ्रा, श्री अन्नपूर्णा इंटरप्राइजेज तथा श्रेया डेवलपर्स जैसी कंपनियों के नाम सामने आए हैं.

सिंधिया समर्थक सीमित, महिलाओं को खास तवज्जो

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को कार्यसमिति में नहीं मिला स्थान

▶ दबाव की राजनीति से अब भाजपा ने किया किनारा

कन्हैया लोधी

भोपाल, 23 जून. लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को भाजपा की बहुप्रतीक्षित प्रदेश कार्यसमिति घोषित कर दी गई. इस कार्यसमिति से भाजपा ने साफ संकेत दे दिया कि अब वह दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी. चाहे दबाव बनाने वाले कितने ही ताकतवर क्यों न हो.

अब भाजपा अपने संविधान के मुताबिक ही संगठन को आगे बढ़ाएगी. वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने महिलाओं को भरपूर तवज्जो देकर ये भी साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का दखल और बढ़ेगा. उन्हें संगठन में 33 फीसदी स्थान देकर ये साफ संकेत दे दिया गया है कि अब लोकसभा और विधानसभा में भी उनकी 33 फीसदी की भागीदारी उनके दहलीज पर ही है. यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो हो सकता है कि संसद के अगले सत्र में ही महिलाओं को संसद और विधासभाओं में 33 फीसदी आरक्षण के साथ परिसीमन संबंधी विधेयक फिर पेश हो सकता है.

भाजपा ने जो प्रदेश कार्यसमिति घोषित की है, उसके लिए सोमवार देर रात मुख्यमंत्री निवास में आला नेताओं के बीच मंथन चला. इस मंथन में ही सूची को अंतिम रूप दिया गया. बताया जा रहा है कि कार्यसमिति में शामिल करने के लिए सिंधिया खेमे की ओर से 15 से अधिक नाम दिए गए थे, उनमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी नाम शामिल था, लेकिन जो सूची जारी की गई, उसमें तोमर का नाम शामिल नहीं है. सिंधिया खेमे से स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी, रक्षा सिरोनिया , गिर्राज दंडोतिया और ओपीएस भदौरिया ही स्थान बनाने में कामयाब हो सके हैं. भाजपा ने इस बार कार्यसमिति में कुल 35 महिलाओं को मौका दिया है. इनमें कांग्रेस से भाजपा में आई सविता दीवान का नाम भी शामिल हैं. एक केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के अलावा प्रदेश की तीन महिला मंत्री को इसमें जगह दी गई है, इनमें संपतिया उईके, निर्मला भूरिया और कृष्णा गौर ही शामिल हैं.

▶ सीएम सहित 17 मंत्री शामिल

कार्यसमिति में सीएम डॉ. मोहन यादव के सहित 17 मंत्रियों को शामिल किया गया है. इनमें दोनों ही उप मुख्यमंत्री के अलावा टॉप फाइव कद्दावर मंत्री भी शामिल हैं. इधर केंद्रीय मंत्रियों में शिवराजसिंह चौहान,सिंधिया, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर को भी शामिल किया गया है. भाजपा के अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के अलावा, नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हैं. मिश्रा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की संभावित टीम के भी दावेदार हैं. कार्यसमिति में अलग- अलग क्षेत्रों के कद्दावर नेताओं को भी शामिल कर शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश की गई है. बुंदेलखंड से गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को स्थाई आमंत्रित में शामिल किया गया है, वहीं महाकौशल से ढाल सिंह बिसेन, गौरीशंकर बिसेन, नीता पटेरिया को पूरा सम्मान दिया गया है.

महज एक मुस्लिम महिला शामिल

भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों की जो सूची जारी की गई है, उमसें महज एक मुस्लिम महिला ही स्थान बनाने में कामयाब हो सकी हैं. सुश्री बिलकिस जहां को कार्यसमिति में सदस्य बनाया गया है.

> **जसपाल अरोरा का नाम चर्चा में**
>
> भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की सूची में एक चर्चित नाम जसपाल अरोरा का भी है. ये भाजपा के कई नेताओं के लिए कानाफूसी का विषय बना हुआ है. मूल रूप से कांग्रेसी अरोरा अब भाजपा के हो गए हैं. बताया जा रहा है कि उनको लेकर स्थानीय स्तर पर ही विरोध शुरू हो गया है. भाजपा के एक और विवादित विधायक संजय पाठक को भी प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों की टीम में शामिल किया गया है.

मादा बाघ शावक को बांधवगढ़ में छोड़ा

उमरिया, 23 जून . उमरिया जिले स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सिवनी से लाई गई एक मादा बाघ शावक को मगधी रेंज के बहेरहा बाड़े में सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया.

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया कि मंगलवार सुबह लगभग पांच बजे मादा बाघ शावक को बहेरहा बाड़े में मुक्त किया गया. यह बाघ शावक सिवनी जिले के दक्षिण वन मंडल क्षेत्र में एक जनहानि की घटना से जुड़ी थी तथा लगातार गांव के आसपास विचरण कर रही थी.उन्होंने बताया कि वन विभाग ने सोमवार को उसे पिंजरे में सुरक्षित पकड़ा था. इसके बाद वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य अधिकारियों की निगरानी में उसे सिवनी से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लाया गया. श्री सहाय ने बताया कि उप संचालक, सहायक संचालक मगधी, वन परिक्षेत्र अधिकारी मगधी तथा सिवनी से आए वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य वनकर्मियों की उपस्थिति में बाघ शावक को बाड़े में छोड़ा गया.

> क्षेत्र संचालक ने बाड़े में उसका निरीक्षण किया, जहां उसकी स्थिति सामान्य पाई गई। उन्होंने बताया कि बाघ शावक आराम से विचरण करती हुई देखी गई है. उन्होंने कहा कि मादा बाघ शावक की वैज्ञानिक तरीके से देखभाल की जाएगी तथा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उपयुक्त समय आने पर उसे पुन: वन क्षेत्र में मुक्त किया जाएगा.

रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई

525 से अधिक लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

मुरैना, 23 जून .राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मुरैना जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक कार्रवाई करते हुए 525 से अधिक लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है.

वहीं अवैध रेत कारोबार से जुड़े 19 लोगों को जिलाबदर किया गया है.पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना के निर्देशन में जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल डावर तथा संबंधित एसडीओपी के मार्गदर्शन में विभिन्न थाना प्रभारियों ने चंबल नदी किनारे बसे गांवों में पहुंचकर अवैध रेत कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की.

हाईकोर्ट में उज्जैन-इंदौर मेट्रो पॉलिटन एरिया को चुनौती

▶ इंदौर और संवैधानिक संस्थाओं के अधिकार कम करने पर उठाए सवाल

नव भारत न्यूज

इंदौर. प्रदेश सरकार ने उज्जैन-इंदौर मेट्रो पॉलिटन एरिया को लेकर जारी की गई अधिसूचना को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की गई है.

एडवोकेट अक्षत पहाड़िया ने याचिका दायर कर अनेक कानूनी बिंदु उठाते हुए कोर्ट को बताया कि कई बिंदुओं की अनदेखी कर ये अधिसूचना जारी की गई. साथ ही नाम में इंदौर को उज्जैन के बाद रखे जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं. हाईकोर्ट की डबल बेंच में उज्जैन-इंदौर मेट्रो पॉलिटन एरिया के अधिसूचना को याचिकाकर्ता एडवोकेट पहाड़िया ने चुनौती दी है. उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य ने एक्ट की धारा 8(1) के तहत 'उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी' का गठन किया है. एक्ट की धारा 3 के तहत महानगरीय क्षेत्र को पहले अधिसूचित करना था, लेकिन अधिसूचना को जारी करने में इसका पालन नहीं किया गया. याचिकाकर्ता ने कहा है कि इंदौर प्रदेश की शैक्षिक, व्यावसायिक और औद्योगिक राजधानी है, जबकि उज्जैन एक धार्मिक और आध्यात्मिक शहर है. दोनों शहर एक-दूसरे से सटे हुए नहीं हैं. दोनों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता.

संवैधानिक आदेश के विपरीत-अथॉरिटी के गठन का प्रावधान है जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं. इसमें अनुच्छेद 243जेडई के तहत बहुत कम संख्या में निर्वाचित सदस्य होते हैं. यह संवैधानिक आदेश के विपरीत है, जिसमें अथॉरिटी द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी. उक्त बिंदुओं को लेकर संशोधन के लिए आवेदन लगाया गया है, जिसमें एक्ट की वैधता और जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है.

ड्रॉफ्ट प्लान पर चर्चा नहीं की

याचिका में 12/6/2026 की जारी अधिसूचना को भी चुनौती दी है जिसके तहत 'मेट्रोपॉलिटन रीजन' घोषित किया गया. साथ ही मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र तय करने से पहले नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत जैसी संवैधानिक संस्थाओं से कोई परामर्श, आपत्ति, सुझाव या ड्राफ्ट प्लान पर चर्चा नहीं की गई. उक्त सभी संस्थाओं की शक्तियां और कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू और अनुसूची 12 में बताए गए हैं. उक्त संवैधानिक संस्थाओं के अधिकार नई सुपर अथॉरिटी को देकर कम किया जा रहा है. यह साफ तौर पर मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.

भिण्ड में दो वाहनों की टक्कर में छह लोग घायल

भिण्ड. भिण्ड जिले के ऊमरी थाना क्षेत्र के खैरा श्यामपुरा गांव के पास हाईवे-552 पर सोमवार को दो वाहनों की टक्कर में छह लोग घायल हो गये. एक इको वाहन भिण्ड से उत्तर प्रदेश के गोपालपुर घाट पर आयोजित घाट पूजन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा था. शाम चार बजे के करीब खैरा श्यामपुरा गांव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसे टक्कर मार दी. हादसे के बाद वाहन सड़क किनारे खाई में पलट गया, जिससे उसमें सवार लोग घायल हो गए. दुर्घटना में छह वर्षीय आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं उसकी 36 वर्षीय मां गुड्कोडी देवी को वाहन का कांच लगने से गंभीर चोटें आईं.

अब जनता नहीं रहेगी बे-बस, 15 अगस्त से सफर की आजादी

▶ जो सड़क बना रहे वही सिटी बस चलाएंगे
▶ उज्जैन दर्शन के लिए चलेंगी एक दर्जन बस
▶ पीथमपुर की आइसर कंपनी में खड़ी बसों को लाया जाएगा शहर

नवभारत न्यूज

उज्जैन. स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से महाकाल की नगरी में 100 इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसें चलाई जाने की तैयारी शुरू हो गई है, प्रथम चरण में 25 बसें सड़कों पर उतारी जाएगी इसके लिए डिपो को भी तैयार किया जा रहा है. हाल फिलहाल सभी बसें पीथमपुर की आइसर कंपनी में खड़ी है.

मुंबई की ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए एलओयू जारी हो चूका है. विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी को ही बस संचालन की जिम्मेदारी देते हुए सीईओ नियुक्त किया गया है. खास बात यह है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण लगभग 15 से अधिक सड़कें सिंहस्थ के तहत बना रहा है. वहीं अब सिटी बस संचालन की जिम्मेदारी भी प्राधिकरण के सीईओ के जिम्मे में कर दी गई है.

इस बार महापौर हुए अलग -नगर निगम के माध्यम से सिटी बस चलाई जाने की कोशिश 2010 से ही शुरू की गई है, कई बार यह योजना बे-पटरी हो गई और एक-एक करके सिटी बस कबाड़ होती चली गई. करोड़ों का भ्रष्टाचार भी हुआ, जाँच भी हुई, नतीजा सिफर रहा. अब एक बार फिर सिंहस्थ 2028 के पहले 100 इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस से चलाई जाने की कवायद की जा रही है. अबकी बार उज्जैन नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल को कंपनी में नहीं रखा गया है. बस कंडक्टर यूसीटीएसएल उपलब्ध कराएगा, किराये और विज्ञापन से होने वाली आय पूरी तरह यूसीटीएसएल की होगी.

सड़कों पर निर्माण और खुदाई -

हालांकि शहर में कई स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण, निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य चल रहे हैं. जगह-जगह खुदाई और ट्रैफिक डायवर्जन के कारण शुरुआती दौर में बस संचालन को लेकर कुछ व्यावहारिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं. इसके बावजूद प्रशासन स्वतंत्रता दिवस से सेवा शुरू करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है.

▶ बस खरीदी में सब्सिडी

यह सारी बसें 40 प्रतिशत सब्सिडी और वायबिलिटी गैप फंड के मॉडल पर ग्रीन सेल कंपनी द्वारा खरीदी जा रही है, जिससे निगम पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा. प्रारंभिक योजना के तहत बसों का संचालन शहर के विभिन्न रूट्स पर होगा. साथ ही 12 बसें विशेष रूप से उज्जैन दर्शन सेवा के लिए आरक्षित रहेंगी. मक्सी रोड स्थित सिटी बस डिपो और कार्यालय परिसर में इन दिनों व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. डिपो से जुड़े अधिकांश कार्य पूरे होने की स्थिति में हैं. उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के सीईओ संदीप सोनी भी इस परियोजना को गति देने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं.

▶ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राहत

हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं. वर्तमान में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच सुगम सार्वजनिक परिवहन की कमी महसूस की जाती है. सिटी बस सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों को कम खर्च में सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा. इससे निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी और शहर के यातायात दबाव में भी कमी आएगी.

सिंहस्थ की तैयारी का अहम हिस्सा-सिटी बस परियोजना को केवल परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि सिंहस्थ-2028 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है. सिंहस्थ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन आएंगे. ऐसे में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है. सिटी बसें भविष्य में सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

मानसून के आने से पहले तेज बारिश

नर्मदापुरम, बड़वानी सहित अन्य जिलों में बारिश

25 जून से प्रदेश में मानसून की एंट्री की संभावना

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 23 जून. मप्र में मानसून के आने से पहले बारिश का दौर जारी है. मंगलवार को नर्मदापुरम, बड़वानी, खरगोन, धार सहित जिलों के अलग-अलग स्थानों पर तेज बारिश हुई.

25 जून से प्रदेश में मानसून के एंट्री की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. प्री-मानसून के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई. बुधवार को प्रदेश के जिलों में बारिश की संभावना को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना में भी तेज बारिश हुई. इससे मौसम सुहावना हो गया, लेकिन किसानों का कहना है कि बोवनी के लिए अभी और पानी की जरूरत है. बुधवार को प्रदेश के सागर, दमोह, बैतूल, खंडवा, छिंदवाड़ा, पांडुराना, नरसिंहपुर सहित जिलों में बिजली कड़कने और मध्यम गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

सेफ क्लिक 2 .0 साइबर जागरूकता अभियान

▶ सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने का उद्देश्य

विशेष संवाददाता

भोपाल. साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे के प्रति नागरिकों को जागरूक बनाने और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस बुधवार को राज्यव्यापी 'सेफ क्लिक 2.0' साइबर जागरूकता अभियान का शुभारंभ करेगी.

रविन्द्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे, जबकि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे. अभियान के तहत विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा आमजन को ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े विषयों पर जागरूक किया जाएगा.

साइबर सुरक्षा एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे. कार्यक्रम में स्कूलों के लिए तैयार साइबर जागरूकता पुस्तिका का विमोचन, अभियान के विशेष वीडियो का अनावरण तथा साइबर सुरक्षा विषय पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जाएगा.

बैठक ▶ अल्पसंख्यक समुदाय से भी बड़ी संख्या में मिला समर्थन

9 लाख सुझाव, 90% यूसीसी के समर्थन में

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 जून. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के लिए सभी जिलों में जन परामर्श बैठकें हो चुकी हैं. सभी जिलों में कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.

राज्य स्तरीय परामर्श 22 जून को भोपाल में हुआ. इसमें सभी आयोगों, विभागों, राजनैतिक दलों और धर्मगुरुओं से अलग-अलग बैठकें आयोजित कर मत लिया गया. लगभग 3.49 करोड़ एसएमएस यूसीसी के सुझाव आमंत्रित करने के लिए समग्र के हितग्राहियों को भेजें गए. नागरिकों के 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं, 90 फीसदी से भी अधिक नागरिक यूसीसी के पक्ष में हैं. अल्पसंख्यक समुदाय का भी बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त हुआ है. विधेयक के प्रारूप पर समिति द्वारा विधि विभाग के साथ साझा रूप से कार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में यह जानकारी दी.

बताया जा रहा है कि बैठक में यह भी साफ कर दिया गया है कि 5 जुलाई को यूसीसी की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी. राज्य सरकार ने हाई पॉवर कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए दो माह का समय दिया था, जिसकी अवधि 27 जून को समाप्त हो रही है.

> **गुरू पूर्णिमा पखवाड़ा मनेगा**
>
> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में गुरू पूर्णिमा पखवाड़ा 15 से 29 जुलाई तक मनाया जाएगा. इस अवधि में सभी स्कूलों में अलग अलग शैक्षणिक, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और गतिविधियां होंगी. इसमें जनप्रतिनिधि, पालक एवं विषय विशेषज्ञ शामिल होगें. इसमें विद्यार्थियों के विकास की कार्य योजना बनाई जाएगी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 19 मार्च से प्रारंभजल गंगा संवर्धन अभियान का 25 से 30 जून की अवधि में समारोहपूर्वक समापन होगा. भारत सरकार के जल संचय जन भागीदारी अभियान में मप्र का तीसरा स्थान है. डिण्डौरी, खण्डवा तथा शहडोल देश के प्रथम 10 जिलों में तथा खण्डवा और इंदौर के नगरीय निकाय, देश के प्रथम 10 नगरीय निकायों में शामिल है. प्रदेश में अभियान में जल संरक्षण एवं संवर्धन में उल्लेखनीय कार्य हुए है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में समारोहपूर्वक समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाए.

पेज एक का शेष

बीजेपी की कार्यसमिति घोषित

उन्होंने कहा कि भाजपा के मूल सिद्धांतों के अनुरूप सभी चयनित कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियों में सक्रिय भागीदारी देने पर जोर दिया गया है. कोठारी ने कहा कि आगामी समय में आवश्यकता अनुसार चर्चा कर विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए जायेंगे. प्रदेश कार्यसमिति में ये शामिल: डॉ. मोहन यादव, शिवराजसिंह चौहान, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जगदीश देवड़ा, राजेन्द्र शुक्ल, डीडी उइके, सावित्री ठाकुर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, वीडी शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरोत्तम मिश्रा, लाल सिंह आर्य, अरविंद भदौरिया, संपतिया उइके, कुंवर विजय शाह, इंदर सिंह परमार, उदयप्रताप सिंह, तुलसीराम सिलावट, एदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविन्द सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाह, चैनत्य कुमार काश्यप, भूपेन्द्र सिंह, कृष्णा गौर, संध्या राय, गणेश सिंह, हिमाद्री सिंह, कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मिकी, माया नारोलिया, बृजेन्द्र प्रताप सिंह, हरिशंकर खटीक, कमल पटेल, गजेन्द्र पटेल, रामेश्वर शर्मा, गिर्राज दंडोतिया, ओपीएस भदौरिया, विपिन गोस्वामी, रक्षा सिरोनिया, अभय चौधरी, इमरती देवी, वीरेन्द्र जैन, नरेन्द्र बिरथरे, महेन्द्र सिंह सिसोदिया, हरिशंकर यादव, विनोद पंथी, ललिता यादव, ममता गुप्ता, गौरव तिवारी, मनीषा पाठक, केपी त्रिपाठी, अखण्ड प्रताप सिंह, मृगेन्द्र सिंह, सरदेन्दु तिवारी, रीती पाठक, कुंवर सिंह टेकाम सहित कई अन्य शामिल थे.

200 करोड़ की हेराफेरी: एलएनसीटी ग्रुप पर छापा

बताया जा रहा है कि एलएनसीटी ग्रुप के शैक्षणिक संस्थानों में फीस, छात्रवृत्ति और एजुकेशनल लोन से जुड़े वित्तीय लेनदेन में कथित अनियमितताएं ईओडब्लू की जांच में सामने आई है. इसके साथ ही छात्रों से बस शुल्क, हॉस्टल फीस सहित ली जाने वाली राशि निजी खातों में ट्रांसफर होने का भी आरोप है. ग्रुप से जुड़े छात्रों की स्कॉलरशिप राशि निर्धारित खातों में जमा करने के बजाय अन्य कंपनियों के खातों में भेजे जाने और जिन खातों में भेजा गया, वह बैंक खाते कल्चुरी कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड का होने का कथित तौर पर खुलासा हुआ है. ग्रुप की जांच करते हुए ईओडब्लू को यह भी जानकारी मिली कि शिक्षा और संस्थागत गतिविधियों के नाम पर लिए गए बैंक लोन का अन्य गतिविधियों में हुआ है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 **RNI Reg. No.7590/60**